3. Consideration and return of the following Bills, after they are passed by Lok Sabha:-

(i) The Finance Bill, 2012. - **Four hours**

(ii) The Appropriation (No.3) Bill, 2012 - **Four hours**

(To be discussed together)

GOVERNMENT BILL

The Chemical Weapons Convention (Amendment) Bill, 2010

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SRIKANT JENA): Sir, I beg to move:

That the Bill to amend the Chemical Weapons Convention Act, 2000, be taken into consideration.

The question was proposed

श्री भुपेन्द्र यादव (राजस्थान): सम्मानीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस उच्च सदन में यह अवसर प्रदान किया है। सम्मानीय महोदय, केमिकल वेपन ऐक्ट का यह जो अमेंडमेंट आया है, यह ऐक्ट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। आज दुनिया में आने वाले समय में, युद्ध को लेकर जो आने वाले खतरे हैं, उसमें केमिकल वेपन, बायलॉजिकल वेपन और न्युक्लियर वेपन, ये तीनों बहुत बड़े खतरे हैं। पहले विश्व यद्ध में दुनिया ने तो तबाही देखी थी, उसके बाद 1925 में, दुनिया में सबसे पहले जिनीवा प्रोटोकॉल में इसका निषेध किया गया था। बाद में, 1997 में केमिकल वेपन का जो कंवेन्शन आया, उसमें हम लोगों ने केमिकल वेपन बिल को, 2000 में, उसके अनुरूप ही Chemical Weapons Convention Act, 2000, पास किया है। अभी इसमें जो संशोधन आया है, सरकार सैक्शन 9 में जो संशोधन लेकर आई है, उसका उद्देश्य यह है कि केमिकल वेपन की जो नेशनल अथॉरिटी है, उस नेशनल अथॉरिटी के कार्य विस्तार को बड़ा करने के लिए यह अमेंडमेंट है।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री प्रशांत चटर्जी)** पीठासीन हुए]

जो केमिकल वेपन कंवेन्शन है, उसके लिए जब एक ऐक्ट, "केमिकल वेपन कंवेन्शन ऐक्ट" है, तब सेम कंवेन्शन के लिए और व्यापक रूप से दूसरा ऐक्ट The Weapons of Mass Destruction and Their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005 है। "केमिकल वेपन ऐक्ट, 2000" में हम लोगों ने केमिकल वेपन कंवेन्शन की जो ट्रीटी है, उससे सम्बन्धित किया है, लेकिन जो Weapons of Mass Destruction Act है, इसमें केमिकल वेपन के साथ बायलॉजिकल वेपन और बाकी न्युक्लियर वेपन के लिए बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों ने इस ऐक्ट को बनाया है। मेरा यह कहना है कि सैक्शन 9 में यह जो

[श्री भुपेन्द्र यादव]

अमेंडमेंट किया गया है, हमने जो नेशनल अथॉरिटी बनाई है, इसके साथ केमिकल वेपन ऐक्ट का जो प्रारूप है, उसमें कहा गया है कि नेशनल अथॉरिटी, जो केमिकल वेपन ऐक्ट में है, वह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस वेपन के बारे में, उसका जो प्रॉक्योरमेंट है, उसका ट्रांसफर है, उसका जो वितरण है, उसके संबंध में अपना व्यू इंटरनेशनल कंवेन्शन केस के साथ साझा करेंगे। इसके साथ-साथ जो Weapons of Mass Destruction Act है, उसमें जो एडवाइजरी कमेटी बनाई है, उसमें केमिकल वेपन की जो नेशनल अथॉरिटी है, उसको मैम्बर बनाया है। परन्तु यहां पर मैं जो बात कहना चाहता हूं, वह यह है कि Weapons of Mass Destruction Act का जो सेक्शन 7 है, उसमें यह कहा गया है, "Whethr a matter falls within the scope of such relevant Act or under this Act, the decision of the Central Government thereon shall be final." मेरी आशंका है कि सेक्शन 9 में आप जिस अथॉरिटी के विस्तार की बात कह रहे हैं, इसकी जो duplicacy होने की संभावना है, वह Weapons of Mass Destruction Act के जो रूल्स हैं, उनमें अभी तक इस बात को provide नहीं किया गया है कि अगर Chemical Weapons Destruction Act के अन्तर्गत सरकार कोई कार्रवाई करेगी, तो Weapons of Mass Destruction Act का जो सेक्शन 7 है, जो Chemical Weapons Destruction Act को overrule करता है, उन दोनों में किस प्रकार का समन्वय रहेगा। इस एक्ट को लेकर यह मेरा पहला विषय है।

दूसरा, Chemical Weapons Act के ऊपर जब स्टैंडिंग कमेटी ने विचार किया, तो स्टैंडिंग कमेटी ने Chemical Weapons Act के खतरों के बारे में भी विचार किया। इसलिए जब स्टैंडिंग कमेटी में यह विषय रखा गया, तो स्टैंडिंग कमेटी का specific question था, "The Committee desires to know whether other Member countries of CWC have enacted the similar legislation for implementation of the CWC treaty." Responding thereto, the Department of Chemicals and Petrochemicals stated, "As per information available at the website of Organization for Prohibition of Chemial Weapons, 83 State Parties have enacted legislation covering all key areas of the Convention." स्टैंडिंग कमेटी ने जब इस बात पर विचार किया था, तो स्टैंडिंग कमेटी ने देश की सुरक्षा को लेकर एक आशंका उठाई थी कि इसके सम्बन्ध में भारत की तैयारी क्या है। जब इस सदन में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स से एक क्वैश्चन पूछा गया था, तो उस क्वैश्चन में यह specifically पूछा गया था कि Whether India has recently ratified the Chemical Weapon Convention without Pakistan having done so? आज स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आई हे, उसके अनुसार दुनिया के केवल 83 देशों ने कंवेशन को ratify करके अपने कानून बनाए हैं। आज के समय में, जब हमें यह पता है कि चीन के पास भी chemical weapon के गैसों के भण्डार हैं, आज के समय में, जब पाकिस्तान में भी इसके ऊपर लॉ नहीं बनाया गया है, तो हमारी सुरक्षा की स्थिति क्या है? इसलिए सदन में जब 19-12-2004 को यह क्वैश्चन पूछा गया था कि "Whether the Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad is in a position to develop soon the facility to test chemical weapons in India in its laboratory?" तो 2004 में इसी सरकार का जवाब था, "No. IICT, Hyderabad is not creating any facilities to test chemical weapons in India. However, IICT has been

participating in the proficiency tests, conducted by the Organisation for Prohibition of Chemical Weapons, Netherlands to get the designation status, so that the chemical in trace levels covered under the Chemical Weapons Convention can also be analysed." मेरा यह कहना है कि सेक्शन 9 के जिस अमेंडमेंट को लाया गया है, वह सेक्शन 9 का अमेंडमेंट इस गम्भीरता को लेकर आया है कि हम अपनी जो नेशनल अथॉरिटी है और chemical weapons की जो चुनौतियां हैं, procurement और उसको check करने की जो चुनौतियां हैं, उनको लेकर देश में ज्यादा अच्छी तरह से कार्यपद्धति विकसित हो। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने National Authority को empower करने के लिए अपनी अथॉरिटी का विस्तार करने का फैसला किया है। पर नेशनल अथॉरिटी को 2000 का एक्ट बनाने के बाद हमने जो power दी थी और हमने जो चाहा था कि देश में केमिकल के लिए एक अच्छी लेबोरेट्री का विकास हो और इसके साथ-साथ देश की सुरक्षा को लेकर भी Chemical Weapons Authority के अंतर्गत regularization हो, उसके सम्बन्ध में कोई सम्भावना नजर नहीं आती है। इसलिए मैंने प्रारम्भ में भी जो कहा कि Chemical Weapons Act और WMD Act में जो overlapping का area है, वह co-ordination का सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए हम लोगों ने Chemical Weapons Act की जो नेशनल अथॉरिटी बनाई है, उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस समय Chemical Weapons Act की नेशनल अथॉरिटी, जिसको सरकार और स्टैंडिंग कमेटी ने देश की सुरक्षा के लिहाज से काफी गम्भीर माना है, क्या सरकार यह बताने की कोशिश करेगी कि नेशनल अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं, वे उसके साथ-साथ Secretary, Performance and Management भी हैं? जब सरकार इस बात को जानती है कि Chemical Weapons की जो नेशनल अथॉरिटी है, उसका एक बहुत बड़ा दायित्व है, ऐसे में उसके नेशनल अथॉरिटी के चेयरमैन के साथ-साथ एक अन्य पद भी होना उचित नहीं है, National Authority में एक dedicated leadership की आवश्यकता है, जिसके बारे में सरकार को जवाब देना चाहिए। दूसरी बात Chemical Weapons Act के अंतर्गत हम लोगों ने जो national authority बनाई है, उसमें हमने Ministry of Defence, Department of Chemical, Foreign Secretary, Secretary of Defence Research, Department of Revenue, Department of Commerce और Chairperson of National Authority for CWC को रखा है। हमने जो Chemical Weapons Act की अथॉरिटी बनाई है, उसमें हमने कहा है कि Chemical Weapon Authority का उद्देश्य mass level पर जो Chemical Weapons हैं, उनको destroy करने के लिए देश की environmental sustainability का ध्यान रखना है। एक तरफ हम लोगों ने इस तरह की National Authority बनाई है, दूसरी तरफ Department of Environment को उस अथॉरिटी से बिल्कुल अलग रखा है। दुनिया के सभी देशों में chemical weapons के लिए जो सबसे concerned department है, वह Department of Environment है, जो इस ऐक्ट से संबंधित है।

दूसरा amendment, जो इस ऐक्ट के संबंध में आया है, वह section-16 और Section-42 का अमेंडमेंट है और वह इस ट्रीटी को harmonize करने के लिए है। Section-18 का जो amendment है, वह भारत की chemical industries के संबंध में है। जो रजिस्ट्रेशन करना है और बाद में उसकी जो जांच करनी है, इसके अंतर्गत उन दोनों को अलग-अलग करने का प्रयत्न किया गया है, जो स्वागत योग्य है।

[श्री भुपेन्द्र यादव]

माननीय महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि कैमिकल वेपन ऐक्ट को केवल एक तरीके से नहीं देखना चाहिए। इस ऐक्ट का जो अमेंडमेंट है, इसके अंतर्गत हमने दुनिया के देशों से संधि करने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है, इसी प्रतिबद्धता के विस्तार के लिए ही यह अमेंडमेंट है, इसलिए यह अमेंडमेंट स्वागत करने योग्य है। लेकिन इस प्रतिबद्धता के साथ-साथ देश की कैमिकल इंडस्ट्री का जो regularization है, वह भी तो हो। इसके साथ-साथ लोगों की सुरक्षा का जो सवाल है, उसके संबंध में हमारे देश के अंदर कैमिकल वेपन के लिए laboratory का विकास भी चाहिए। Standing Committee ने भी अपनी रिपोर्ट में बार-बार यह प्रश्न किया है कि देश के आम नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से हम इस ऐक्ट और इस कन्वेंशन के नाते कितने प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं? इसके संबंध में भी सरकार को ज्यादा गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा Chemical Weapon Act के अंतर्गत हमने जो WMD Act बनाया है, उसके लिए उचित data bank के process करने के विषय को आगे बढ़ाना चाहिए, साथ ही लैबोरेटरी के काम को भी आगे बढ़ाना चाहिए।

दोनों ऐक्ट्स को पढ़ने के बाद, दोनों एक्ट्स में जो duplicacy आ रही है, उसके लिए सरकार ने दोनों ऐक्ट्स में अलग-अलग अथॉरिटी बनाने का प्रयत्न किया है, लेकिन हमारे देश में जो multi-authority बन रही है, उसके कारण प्रशासनिक खर्चा भी बढ़ा है। इस ऐक्ट और कन्वेंशन के साथ-साथ Chemical Weapons Convention Act के isolation में न पड़ कर उसे biological weapons convention और neclear weapons convention के साथ देखना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी युद्ध और आक्रमण जैसे शब्दों को बहुत व्याख्यायित किया है। हो सकता है कि युद्ध पड़ोसी देशों के साथ लड़ा जाता हो, लेकिन जो आक्रमण शब्द है, उसमें state player के साथ जो non-state player हैं, उनका खतरा सबसे ज्यादा है। इसलिए chemical weapons और biological weapons की treaty करते समय दुनिया भर में इस बात की आशंका व्यक्त की गई है कि इसमें state के साथ जो non-state player हैं, उनका एक्टिव रोल देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मेरा यह मानना है कि जो अमेंडमेंट किए गए हैं, ये उसी को विस्तारित करने के लिए किए गए हैं। लेकिन इस अमेंडमेंट के साथ-साथ सरकार को चाहिए कि कोई permanent High Power Coordination council बनें, ताकि दोनों ऐक्ट्स की जो duplicacy है, उसे रोक करके हम इस अमेंडमेंट के साथ इस विषय को प्रभावी रूप से ले सकें। इतना कह कर मैं अपने विषय को समाप्त करता हूं।

श्री नरेन्द्र बुढानिया (राजस्थान): धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज यह जो कैमिकल वेपन संशोधन विधेयक पेश हुआ है, इसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं और इसका स्वागत भी करता हूं।

महोदय, यह जो विषय है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जब पूरे विश्व के अन्दर हथियार बनाने की होड़ लगी है, तो सब लोगों ने यह चिंता व्यक्त की है कि आज जिस प्रकार से ये कैमिकल वेपन्स और बालॉजिकल वेपन्स बन रहे हैं या परमाणु हथियार बन

रहे हैं, ये विश्व के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। कैमिकल वेपन्स को इनमें बहुत ही खतरनाक माना गया है। एक गोली से सिर्फ एक आदमी का नुकसान होता है या अन्य किसी वेपन से एक सीमित नुकसान होता है, लेकिन कैमिकल वेपन ऐसा वेपन है, जिसका कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है कि यह कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रख कर सन् 1993 में पेरिस में सारे देश इकट्ठा हुए। वहां इस गम्भीर विषय के ऊपर विचार किया गया और इस खतरे को ध्यान में रखते हुए वहां पर एक समझौता हुआ, एक ट्रीटी हुई। उस समझौते में अग्रणी रहकर भारत ने उस पर हस्ताक्षर किया। महोदय, उस वक्त 190 देशों ने उस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए और छः देशों ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। वे बहुत छोटे देश थे। अंगोला, इजिप्ट, सोमालिया, सीरिया, नॉर्थ कोरिया और सूडान ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। उस ट्रीटी को मजबूत करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 2000 में एक अधिनियम बनाया। मुझे खुशी है कि उस ट्रीटी के मुताबिक भारत के अन्दर chemical weapons को नष्ट करने का निर्णय लिया गया और भारत ने chemical weapons पूरी तरह से नष्ट कर दिए।

महोदय, जब हम chemical weapons की बात करते हैं, हानिकारक chemicals की बात करते हैं, तो हमारे सामने भोपाल कांड आता है। भोपाल की जो त्रासदी हुई, उस त्रासदी को जब हम आज याद करते हैं, तब सबके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है और इस विषय पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जो हानिकारक केमिकल्स बनाते हैं, इसकी एक विशेष मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। वहां कौन-कौन से केमिकल्स बनते हैं, कितनी मात्रा में बनते हैं, उसकी सप्लाई कहां-कहां करते हैं, उनका उपयोग किस-किस काम में करते हैं और किस-किस को ये सप्लाई करते हैं। इस चीज के मॉनिटरिंग की बहुत आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने इस दिशा में अनेक कदम पहले भी उठाए हैं और आज यह जो अमेंडमेंट आया है, यह इसी दिशा में इसे और आगे बढ़ाने के लिए आया है।

अभी मेरे एक साथी ने इसकी धारा 9 के बारे में कुछ बातें बताईं। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मुझे भी बोलने के लिए पांच मिनट का ही समय दिया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि धारा 9 की उपधारा (1) में नेशनल अथॉरिटी को प्रवर्तन अधिकारी बनाने की जो पावर दी गई है, उसको और आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार इसमें यह अमेंडमेंट लेकर आई है कि भारत सरकार किसी भी उपयुक्त अधिकारी को इस काम में लगा सकती है। यह एक अच्छा निर्णय है। इससे काम करने में और ताकत मिलेगी। जो हानिकारक रसायन हैं, विषैले रसायन हैं, शैड्यूल्ड 2 के अन्दर उनकी एक लिस्ट बनी हुई है। जो इस लिस्ट का उल्लंघन करता है, जो ऐसे हानिकारक रसायन बनाता है, उसके लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि इसमें आजीवन कारावास का प्रावधान रखा गया है। और एक लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है।

महोदय, इसके ऊपर और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज यदि हमारे सामने कोई ज्वलंत विषय है, तो इसी प्रकार का है कि आज हमारी इस इंडस्ट्री के अन्दर लोग ऐसे काम तो नहीं कर रहे हैं, जिनसे ऐसे हथियार बन जाएं, जिनका दुरुपयोग हो जाए और वे हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा हों। आज ऐसा जहर जो पैदा हो रहा है, यह हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर इस

[श्री नरेन्द्र बुढानिया]

प्रकार के कैमिकल्स बन रहे हैं, वहां से जब हम गुजरते हैं तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वहां के आसपास जो लोग रहते हैं, उनका जीना दुर्लभ हो जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर इसकी मॉनिटरिंग के लिए यह जो नेशनल अथॉरिटी है, इसको और मजबूत बनाया जाए। इसे और मजबूत बनाते हुए इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाए, ताकि हमारे देश के अन्दर हमें एक और भोपाल-जैसी त्रासदी का सामना करना नहीं पड़े तथा ऐसा कोई नुकसान हमारे सामने नहीं आए।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन देशों ने इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं, वे सारे देश इसका पूर्ण रूप से पालन करें, इसके लिए भारत सरकार को आगे होकर इन देशों पर दबाव बनाना चाहिए। कुछ बड़े देश हैं, जिन्होंने इस पर अभी तक काम पूरा नहीं किया है या जिन्होंने अपने chemical weapons पूर्ण रूप से नष्ट नहीं किए हैं, उन देशों के ऊपर भी दबाव बना कर उनके chemical weapons को नष्ट करवाना चाहिए। यही बातें कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): Sir, the original Bill establishes a national authority to implement the provisions of the International Convention on Chemical Weapons. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW, has 188 countries as member-states. I want to know from the Minister: How many countries have made legislation to fulfil the provisions contained in the International Convention?

Sir, this amendment Bill intends to give more powers to the Government. I support the international initiative to destroy the chemical weapons. As per the new decision of the OPCW, the final deadline for complete destruction of remaining chemical weapons was extended to 29th April 2012. Now, this is over. It was reported that India had completed its destruction of existing weapons in 2009 and it was also reported that our country still have some facilities for producing chemical weapons. I want to know the present status of it. Whether this report is correct or not?

Sir, I want to know one more point. What about the position of other countries to fulfil the commitment of International Convention? In January 2012, the United States of America finished destroying 20 per cent of the chemical weapons and two new chemical weapon production sites were under construction. The US Ambassador to this international forum had acknowledged that it will take as long as 2021 to finish destroying the final ten per cent of chemical weapons. Actually, the United States of America has used chemical weapons wherever, they needed. We have the experience of Vietnam War where they used 'Agent Orange' which contained one of the most virulent poisons known to man, a strain of dioxin called

TCCD. After three decades of that War, more than five lakh children have born with birth disabilities and defects. The US has also used these chemical weapons scenario for invasion. They alleged that Iraq had some Weapons of Mass Destruction and chemical weapons and created a situation for invasion into that country. I would not like to take more time on these details.

Sir, while coming to this amendment Bill, I have certain objections regarding the exemption of registration. It gives the Central Government more power to make registration mandatory subject to certain threshold limit which may be prescribed by the Government. Actually, this amendment Bill gives more power to the Executive and I suspect, it will open more avenues for corruption. That is the reality in our country. Wherever we fix some threshold limit, it would open more avenues for corruption to some bureaucrats.

Sir, several chemical companies would be free from compulsory registration. This would lead to dangerous situation. Chemical weapon is the simplest form in the Weapons of Mass Destruction. Anybody can produce a chemical weapon from materials which can be produced in small factories also. There are two types of chemical weapons, persistent and non-persistent. Some small factories can be used for producing these types of chemical materials which can be used for producing chemical weapons. These new criteria forcing a threshold limit would create several problems and it would lead to production of chemical weapons. It is a dangerous situation. I request the Minister to reconsider that amendment to prescribe a threshold limit. It would create a serious problem to the security of the country; to the security of the human being and also create more avenues for corruption to some officials. Sir, we have made several new Acts after the Bhopal gas tragedy. Before that we had no specific Act to get any compensation. Thereafter we have made several Acts for insurance and compensation. But now also the existing Acts are not sufficient to address these types of things. So, I request the Minister to revisit the entire legislation with regard to the chemical weapons and with regard to compensation issues whether it is sufficient to address the existing scenario in our country. I hope the Minister will consider this suggestion favourably; and withdraw that part of the amendment wherein he prescribed a threshold limit for the registration. Thank you.

SHRI D. BANDYOPADHYAY (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Chemical Weapons Convention (Amendment) Bill, 2010. I support this Bill because it fulfills our obligation to the international convention to which we were a signatory. If I read the convention, it says, "The Convention on the

[Shri D.Bandyopadhyay]

prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons and on their destruction...". The convention is not only for use or stockpiling, but also for destruction. So, we, as a nation. Believing in the principle of non-violence and take the initiative of unilaterally destroying our own chemical weapons which are available and set an example to the world? I am not saying that do not give up your ability to produce because if there is a threat, you have to produce, you can't help it. But can we take that unilateral action to destroy chemical weapons by taking Mahatma Gandhi and Nehruvian attitude on non-violence? While I fully support the Bill, I have some suspicion or fear that subject to such exemption etc., if we give exemption, could this lead to the leakage of dangerous chemical weapons to subversive elements, particularly the terrorists who are carrying on a proxy war, on behalf of somebody else, in our country? While I am fully supporting the empowerment of the Government to do so, I am totally against giving any exemption to anybody excepting direct Government functionaries or Government units which are involved in whatever activities they are. With these words, Sir, I support the Bill, but. I will urge India to take unilateral stand for destroying all chemical weapons.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Shrimati Vasanthi Stanley, not present. Next, Shri Baishnab Parida.

SHRI BAISHNAB PARIDA (Odisha): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for allowing me to say a few words in favour of the amendment of the Bill.

[**THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN)** in the Chair]

Sir, India is one of the primary Signataries of the international convention to destroy chemical weapons from the face of the earth. India is one of the first countries which had ratified the convention and made legislation to destroy, control and to regulate the chemical weapons. After long years of international movement against arms race, the peace loving countries of the world took the decision to destroy and prevent further production of harmful weapons. Like atomic weapons and biological weapons, the chemical weapons are the most dangerous for the existence of humanity. Sir, in this Bill, the hon. Minister has tried to make stringent provisions to regularise the chemical industry in the country and to prevent and save the environment from its harmful effects. The formation of national authority to implement the provisions of the treaty is a positive step in this direction. Restriction of transfer of toxic chemicals and precursors listed in Schedule 2 is very practical. I

think it is desirable. Sir, I don't want to make a long speech, but for the interest of the country and to fulfil our promise to the international community, this Bill enhances the prestige of India as a peace loving country. Thank you.

SHRI SANJAY RAUT (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Chemical Weapons Convention (Amendment) Bill, 2010. The Bill is long overdue in view of internal and external threats. In fact, the Bill was introduced in the Rajya Sabha in April, 2010. Then, it was referred to the Parliamentary Standing Committee on Chemicals and Fertilizers. The Bill seeks to amend the Chemical Weapons Convention Act, 2000, which was passed to give effect to the Convention on the prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons, and on their destruction India signed the Convention in January, 1993. The Bill to amend the Act was introduced in the Lok Sabha, in April last, to bring the legislation in line with the international convention. The Standing Committee strongly felt that the threat perception, both internal and external, being faced by the country needs to be given due consideration. I think the Government has given a serious thought to incorporate in the proposed Bill suitable provisions for the safety and security of the country and its people in the event of a chemical warfare. But I want to know from the hon. Minister whether the Government has carried out or proposes to carry out a mock drill in any part of the country in case of a chemical warfare. The Government should enlighten the countrymen about the chemical war perception. I do not know whether RDX comes under the purview of this Bill. In recent years, we have seen terrorists using RDX to kill innocent people in the country. Even the sale of this type of chemical should be regulated. What about the gelatine sticks being used by the Naxals in some States? If it is not covered under the purview of the Bill, the hon. Minister may consider this also.

Sir, the Bill envisages the Government to appoint any of its officers as the authority to monitor and regulate production and transfer of those chemicals which could be used for dirty weapons. May I know what will be their qualification and experience? The Government should prescribe a heavy penalty for officers who would succumb to gratification in dealing with dirty weapons. The Government should also work in tandem with other countries for elimination of chemical weapons on the lines of nuclear arsenal.

With these words., I support the Bill. Thank you.

SHRI M. RAMA JOIS (Karnataka): Sir, the Statement of Objects and Reasons say, "The Convention on the Prohibition of the Development, Production,

[Shri M. Rama Jois]

Stockpiling and use of Chemical Weapons and on their Destruction was singed on behalf of the Government of India at Paris on the 14th day of January, 1993. The Chemical Weapons Convention Act, 2000, was enacted to give effect to the said Convention." It is in conformity with the ancient wisdom. Sometimes, we always consider 'Dharma' means religion. But, it is not religion. Dharma means, for everything there is a code of conduct. When I wrote this Legal and Constitutional History between 1970 and 1982 *i.e.*, for 12 years, I found that there were war regulations. In that, it is stated,

"न कूटैरायुधैर्हन्याद्युध्यमानो रणे रिपून्।
न कर्णिभिर्नापि दिग्धैर्नाग्निजवलिततेजनैः।।"
"एषोअनुपस्कृतः प्रोक्तो योधधर्मः सनातनः।"

(Manusmriti VIII 90 and 98)

These are the rules to be followed during wars and the human rights have to be given the highest importance. The meaning is, let not the king strike with concealed weapons nor weapons which are barred, poisoned—chemical weapons—or the points of which are blazing with fire. This is in the *Manu Smrithi* Even while engaging in war, we have to follow certain Dharma, rules and one should not use all these weapons. I think, the prohibition of use of chemicals weapons is in conformity with that principle of Dharma laid down in our war regulations. For instance, had the atomic bomb was not in the hands of the USA but if it was in the hands of India, we would not have bombed Hiroshima and Nagasaki, because our culture or Dharma does not permit destruction of human beings through such methods. So, the wisdom was found in our ancient regulations regarding chemicals, poisonous and blazing weapons. Thank you.

DR. NAJMA A. HEPTULLA (Madhya Pradesh): Sir, very ably one of our new Members of the House supported the Bill and spoke on every Clause of the Bill.

I only want to bring to the notice of the hon. Minister and the Government that the Bill is regarding chemicals weapons. But, Sir, we know that there are certain hazardous chemicals produced by many industries. For example, in Bhopal, when we had the horrendous gas tragedy on December 2-3, 1984, thousands of people died. One does not even know whether there were 10,000 or 20,000 or 50,000 deaths, because all the people in that particular area died. I remember it. I was here in the House as Deputy Chairman. I had a group of four young scientists working with me on various issues. Those four scientists went to Bhopal after the tragedy. The company was supposed to manufacture pesticides, but what kind of pesticides it

was manufacturing. I am saying this because the gas leak affected the people for generations. Now, I think, even the second generation of children might have been born. The affects are not that of Methyl Isocyanate gas about which people were talking about. The results were quite different. The affects were quite different. One wouldn't know; it could be some nerve gas being manufactured under the garb of manufacture of pesticides. So, I would like to know something from the hon. Minister. Of course, this Convention was not there at that time. (*Interruptions*) I will take only one minute. It is a serious matter, Sir. While the chemical weapons would be registered...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): The Minister has to go there; there is guillotine at 6 p.m.

DR. NAJMA A. HEPTULLA: I will take just one second, Sir. Now, under this Convention, the authority can inspect that.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Madam, he has to go. We will just pass it.

DR. NAJMA A. HEPTULLA: I will put only one question to the Minister. Under the garb of manufacture of a non-hazardous material, they might be manufacturing a hazardous material which could be used as a chemical weapon. So, the Government should take upon itself this responsibility in respect of not only those factories which are registered under the Chemical Weapons Act but also those units which are manufacturing chemicals in other industries. You must have this provision. They could be testing those materials. People should know what really are they manufacturing, and whether they have got their registration done for the same purpose or not.

SHRI SRIKANT JENA: Sir, I thank all the hon. Members who have participated in this debate. This is a Bill amending the original Act. It was introduced in 2010. It went to the Standing Committee. The Standing Committee made certain recommendations. We adopted those recommendations of the Standing Committee and, accordingly, we have moved this.

Sir, I have taken note of the concerns expressed by hon. Members. This is an international obligation which we have to meet because, as has been rightly: said, India is a signatory to this Convention. So, we are fulfilling those international obligations. I hope all the hon. Members will cooperate in the passage of this Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, I put the motion to vote. The question is:

"That the Bill to amend the Chemical Weapons Convention Act, 2000, be taken into consideration."

The motion was adopted

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill. Clause 2 stands part of the Bill. There is one Amendment (No. 3) by Shri Srikant Jena.

Clause 2—Amendment of Section 9

SHRI SRIKANT JENA: Sir, I move:

(No. 3) That at page **2, for** lines **2** and **3**, the following be **substituted**, namely:-

"Principal Act, in section 9, in sub-section (1),

(a) after the words "National Authority", the words "or of the Central Government" shall be inserted;

(b) the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that such officers shall fulfil the prescribed criteria."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. PJ. KURIEN): Now, we shall take up Clause 3. There is one Amendment (No. 4) by Shri Srikant Jena.

Clause 3—Substitution of new section for section 16

SHRI SRIKANT JENA: Sir, I move:

(No. 4) That at page **2**, line **7**, **after** the words "**the Convention**", the words "**or** any person who is not a citizen of a State Party" be **Inserted**.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

Clause 4 was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. PJ. KURIEN): Now, we shall take up Clause 5. There is one Amendment (No. 5) by Shri Srikant Jena.

Clause 5—Amendment of section 42

SHRI SRIKANT JENA; Sir, I move:

(No. 5) That at page **2**, for lines **23** and **24**, the following be **substituted**, namely:-

"5. In section 42 of the principal Act, for the words "any person", the words "a State which is not a State Party or any person" shall be substituted."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 5, as amended, was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. PJ. KURIEN): Now, we shall take up Clause 6. There is one Amendment (No. 6) by Shri Srikant Jena.

Clause 6—Amendment of section 56

SHRI SRJKANT JENA: Sir, I move:

(No. 6) That at page **2**, for lines **25** and **26**, the following be **substituted**, namely:-

"6. In section 56 of the principal Act, in sub-section (2):-

(a) after clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

"(ba) the criteria which the officers are required to fulfil under sub-section (1) of section 9";

(b) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-"

The question was put and the motion was adopted.

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. PJ. KURIEN): Now, we shall take up Clause 1. There is one Amendment (No. 2) by Shri Srikant Jena.

Clause 1—Short title and commencement

SHRI SRIKANT JENA: Sir, I move:

(No. 2) That at page **1**, line **3**, **for** the figure "**2010**" the figure "**2012**" be **substituted**.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): There is one Amendment (No. l) to the Enacting Formula.

Enacting Formula

SHRI SRIKANT JENA: Sir, I move:

(1) That at page **1**, line **1**, **for** the word "**Sixty-first**", the word "**Sixty-third**" be **substituted**.

The question was put and the motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI SRIKANT JENA: Sir, I move:

That the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. PJ. KURIEN): Now, the House stands adjourned till 11 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at fifty-six minutes past five of the clock till eleven of the clock on Friday, the 4th May, 2012.